## सच्चे देशभक्तों से माओवादियों की अपील

# अर्ध सैनिक बलों द्वारा सेना की मदद से चलाए जाने वाले आगामी फासीवादी सैनिक दमन अभियान के विरोध में

# 26 जनवरी 2014 - गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रुप में मनाओ!

## देश की सेना को - देश की ही जनता के खिलाफ उतारने के विरोध में आवाज उठाओ!

## देश की खनिज संपदाओं को विदेशी कंपनियों व दलाल पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए ही ऐसे सैनिक अभियान चलाए जा रहे हैं!

**सच्चे देशभक्त जनवाद प्रेमियो**

26 दिसंबर 2013 को आपरेशन ग्रीनहंट 'जनता पर युध्द' का तीसरा चरण शुरु हो गया है. इस दिन 40 हजार अर्ध सैनिक बलों के नेतृत्व में और वायु सेना के दर्जनों सैनिक एमआई-17 हेलिकाप्टरों, ड्रोन विमानों, राकेट लांचारों, जीपीएस सेटों आदि अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर एक सैनिक अभियान चलाया गया. यह पहला मौका था जब देश की जनता के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर बाकायदा घोषणा करके युध्द ऐलान किया गया. यह एक देशव्यापी हमला था, जिसने अंदुरुनी हिस्सो में जनजीवन में दहशत फैलाई और जनता को अपने दैनिक कामकाज निपटाना भी मुश्किल हो गया. और अब 14 जनवरी 2014 को फिर सीआरपीएफ के डीजीपी ने ओड़िशा समाचारों में घोषणा की है कि पहला अभियान सफल रहा अब एक लाख की संख्या में सशस्त्र बलों को तैनात कर अभियान चलाया जायेगा, ताकि माओवादियों पर दबाव डाला जा सके और वह आत्मसमर्पण करके वार्ता के लिए आगे आ सकें. उसका कहना है कि इस नए अभियान से माओवादियों की कमर तोड़ दी जायेगी. सच्चाई यह है कि चालिस हजार की संख्या से चलाया गया दमन अभियान पूरी तरह से विफल हुआ है. हमारी पार्टी की जनता ने भरपुर मदद की जिस कारण से सैनिक बलों को कोई सफलता नहीं मिली. इसलिए दोबारा फिर उन्हें एक नए दमन अभियान को शुरु करने की घोषणा की है.

इस ऐलान से पहले ओड़िशा के मुख्यमंत्री व विदेशी कंपनियों के दलाल नवीन पटनायक ने घोषणा की थी कि कोरापुट, बलांगीर, बरगढ़, मलकानगिरी, कालाहांडी, रायगढ़, सुंदरगढ़, नुआपाड़ा, नवरंगपुर, संबलपुर जिलों में माओवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं. माओवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. और अभी-अभी दक्षिण कोरिआई प्रधानमंत्री भी देश के दौरे पर हैं, जिसके साथ बड़े पूंजीपतियों का दल भी है. इसमें पोस्को कंपनी का अध्यक्ष भी आया हुआ है. यह वही कंपनी पोस्को है जो ओड़िशा में कई सालों से जनता के विरोध के बावजूद खदान खोलने पर आमदा है और इतना ही नहीं केंद्र व राज्य सरकारें उसके लिए लाल कालीन बिछा रही हैं. पर्यावरण मंत्रालय ने भी उसको एक दिन पहले मंजूरी दे दी है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद रमन सिंग भी जीत के नशे में चूर होकर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को बेचेने के लिए विदेशी कंपनियों का जोर शोर के साथ स्वागत कर रहा है.

**आज हर सच्चे देशभक्त का कर्तव्य बन जाता है कि इस घटनाक्रम को समझे कि क्यों लाखों जनता की कुर्बानी की बदलौत जिन विदेशी कंपनियों को भगाया गया था उनका देश के शोषक-शासक वर्ग स्वागत कर रहे हैं और क्यों सैनिक अधिकारी अपनी ही जनता पर अंग्रेजों की तरह जुल्म ढहाने के लिए सैनिक अभियान की घोषणा कर रहे हैं.**

हमारी राज्य कमेटी इस अभियान का कड़ा विरोध करती है. शासक वर्गों को चेतावनी देती है कि वह माओवादी पार्टी को सरेंडर करवाने के ख्याली पुलाव न पकाये. आखिरी सांस तक जनता की जन सेना के योध्दा उसकी व उसके आंदोलन की रक्षा करेंगे. जनता की व्यापक मदद से इस तरह के अभियानों को हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा है. सलवा जुडूम इसका ताजा उदहारण है.

**दोस्तो**

आज पूरा देश जानता है कि माओवादी संघर्षरत इलाके आदिवासी बहुल इलाके हैं. छत्तीसगढ़, झारखंड हो या ओड़िशा सभी खनिज संपदाओं के अकूत भंडारों से भरे हुए राज्य हैं. यहां की आदिवासी जनता पूरी तरह से जल-जंगल-जमीन पर निर्भर है. हमारे राज्य ओड़िशा में कदम-कदम पर बॉक्साईट, लोह और गरेफाइट आदि के भंडार हैं. पूरे राज्य को नवीन पटनायक बेच चुका है, इस संपदा को निकलाने के लिए टाटा, बिड़ला, वेदांता, पोस्को, स्टारलाईट, सेल आदि कंपनियों से एमओयू कर चुका है. काशिपुर, जगतसिंगपुर, नियमगिरी सहित पूरे राज्य में जनता विस्थापन के खिलाफ

संघर्षरत है. नियमगिरी के आसपास चार ब्लॉकों में 10 से ज्यादा कंपनियों से एमआयू हुए हैं जिनमें वेदांता भी एक है. वेदांता की नियमगिरी में हार के बाद उसे इसी के आसपास कुंडनमाली व सुजीमाली (पहाड़) को देने की मंजूरी राज्य व केंद्र सरकार ने दी है. नियमगिरी के बाद गंदमर्दान पहाड़ बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार है जहां पर 213 मिलियन टन बॉक्साइट है. आने वाले समय में कालाहंडी व रायगढ़ विदेशी कंपनियों व दलाल पूंजीपतियों के सबसे बड़े लूट के केंद्र बनने वाले हैं. इन दो जिलों में 40 से ज्यादा कंपनियों से राज्य सरकार ने एमओयू साइन किये हैं. आज सभी ये भी जानते हैं कि आर्थिक संकट के चलते सभी बड़ी-बड़ी विदेशी व दलाल पूंजीपतियों की कंपनियों का मुनाफा घट रहा है, इसलिए उनको अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए सस्ता कच्चा माल चाहिए और वह छीपा हुआ है आदिवासी इलाकों, आदिवासी इलाकों में माओवादी पार्टी के नेतृत्व में जनता यह देने के लिए तैयार नहीं है. आदिवासी जनता यहां सच्चे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है. काशिपुर, जगतसिंगपुर आदि में टाटा, हिंडालको वर्षों से जनता का दमन कर रहे हैं, नियमिगरी में वेदांता के मंशूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और पोस्को को भी खाली हाथ बैठना पड़ रहा है. इसलिए बड़े पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर उनसे मोटी दलाली लेकर ओड़िशा की नवीन पटनायक सरकार की तरह सभी राज्यों की सरकारें व केंद्र की यूपीए-2 जनता पर युध्द लाद रही हैं. इसलिए तमाम देशभक्तों को समझ लेना चाहिए है कि **यह युध्द देश की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों के मुनाफ के लिए लड़ा जा रहा युध्द है. यह युध्द देश के दुश्मनों के खिलाफ नहीं, देश के नागरिकों के खिलाफ लड़ा जाने वाला युध्द है. आज माओवादी ही नहीं विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाली जनता, अपनी जल-जंगल-जमीन के लिए लड़ने वाली आदिवासी जनता व उसका समर्थन करने वाली हर ताकत फासीवादी ग्रीनहंट के निशाने पर है.** माओवादी संघर्षरत इलाकों में पहले से तैनात 3 लाख 50 हजार सशस्त्र बलों के अलावा और एक लाख सशस्त्र बलों की तैनाती से पूरी तरह देश को मनमोहन, चिदंबरम, सुशीलकुमार शिंदे, सोनिया गांधी, रमन सिंग व नवीन पटनायक जैसे लूटेरे युध्द में डूबो देना चाहते हैं. पता नहीं कितने सार्किनगुड़ा, एड़समेट्टा जैसे नरसंहार करने पर आमदा हैं.

**सच्चे देशभक्तो**

माओवादी पार्टी देश की सच्ची आजादी के लिए लाखों जनता का नेतृत्व करते हुए संघर्षरत है. उसने हजारों नेताओं, योध्दाओं, नौजवानों की शहादत ही देश की जनता की खुशहाली के लिए दी है. उसके नेतृत्व में जनता ने व्यापक इलाके में अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा की, कई विदेशी व पूंजीपतियों की कंपनियों की लूट से बचाया है. विस्थापन के खिलाफ एक बड़ी ताकत के रुप में उभरी है. वह इस शोषक व्यवस्था के खिलाफ एक शानदार विकल्प प्रस्तुत कर रही है यही वजह है कि आज वह तमाम विदेशी कंपनियों, बड़े पूंजीपतियों व शोषक लूटेरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन गयी है. इस लिए आप्रेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण को शुरु करते हुए इतने बड़े सैनिक अभियान की घोषणा शाषकों ने की है.

इस युध्द की सफलता से पूरा देश एक बार फिर साम्राज्यवादियों, विदेशी कंपनियों का गुलाम बन जायेगा. देश की जनता अपने जल-जंगल-जमीन व खनिज संपदाओं से हाथ धो बैठेगी, तमाम जन आंदोलनों को सरकार कुचल डालेगी और पूंजीपतियों-सामंतों का एक छत्र राज कायम हो जायेगा. विरोध की हर आवाज दफन हो जायेगी. इसलिए आज सभी नागरिकों के सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि वह इस युध्द के खिलाफ हैं या इसके समर्थन में. आज देशभक्तों को चाहिए कि विदेशी कंपनियों, पूंजीपतियों के फायद के लिए लड़े जाने वाले युध्द का विरोध करें. हम देश के तमाम नागरिकों, छात्रों, किसान-मजदूरों, दुकानदारों, बुध्दिजीवियों से अपील करते हैं कि इस अन्यायपूर्ण युध्द के खिलाफ 26# जनवरी 2014 के गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रुप में मनाएं.

सच्चे देशभक्त सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों से अपील करते हैं कि वह सरकार की साजिश को समझें, अपने ही देश की गरीब जनता पर युध्द में न उतरें, पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों के लिए बलि के बकरे मत बनें!

अर्ध सैनिक, सैनिक व पुलिस बलों के जवानों के माता-पिता व भाई-बहनों से अपील है कि अपने बेटों को अपने ही भाईबंदों पर गोली चलाने से रोकें, देश की जनता के खिलाफ उनकी तैनाती के विरोध में एकजुट हो आंदोलन करें.

भारत के जनयुध्द के समर्थन में काम कर रही तमाम क्रांतिकारी, प्रगितीशील, आदिवासी शुभचिंतक ताकतों से हम अपील करते हैं कि इस तरह के अभियानों के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जनमत तैयार करें और ऐसे अभियानों की कड़ी भर्त्सना करें.

**15 जनवरी 2014**

**ओड़िशा राज्य कमेटी**

# भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)